List of Parliament Unstarred question (Lok Sabha and Rajya Sabha)and answer prepared by CA Unit

From 2011-2016

S.No.	Q.No.	Starred/Unstarred	Raised by	Subject	File No.
1	LS-3899	Admitted (Unstarred)	Sh. Ashok Shankarrao Chavan, Sh. Sudheer Gupta, Sh. S.R. Vijayakumar, Sh. T. Radhakrishnan, Sh. Kunwar Haribansh Singh due for reply on 09.08.2016	Sesame seed production	4-3/2016/ Oilseeds/CA
2	LS-2515	Admitted (Unstarred)	16.08.2011, Sh. Hrishchandra Chavan	Minikit seed programme	4-4/2011/P/TMOP
	LS-Total 02				
1	RS-582	Admitted (Unstarred)	Shri Meghraj Jain due for reply on 22.07.2016	Improving the farming of pulses and oilseeds	4-1/2016/Oilseeds/CA
2	RS-2455	Unstarred (admitted)	01.08.2014 Shri Prabhat Jha & Vijay Goel	Effect of delayedmonsoon on sowing of soybean	4-2/2014/OSMM-I/CA
3	RS-4675	Admitted (Unstarred)	18.05.2012, Sh. Dilipbhai Pandya	Minikit seeds programme	4-2/2012-AAP /TMOP (KB)
	RS-Total 03				
	G. Total 05 (LS+RS)				

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.3899
TO BE ANSWERED ON THE 9TH AUGUST, 2016

SESAME SEED PRODUCTION

3899. SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN:
SHRI SUDHEER GUPTA:
SHRI S.R. VIJAYAKUMAR:
SHRI T. RADHAKRISHNAN:
KUNWAR HARIBANSH SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री be pleased to state:

(a) whether India is the world's largest sesame seed producer and if so, the details thereof;

(b) the details of the total foreign exchange earned by the Government in this regard during each of the last three years and the current year;

(c) whether some countries are reluctant to import Indian sesame seed in their country due to excessive use of pesticides and insecticides in the cultivation of sesame in the country and if so, the details thereof;

(d) the steps taken by the Government to encourage the farmers to use pesticides/insecticides as per permitted global norms and if so, the details in this regard; and

(e) the other steps taken/to be taken by the Government to make the farmers shift to organic farming of sesame seed in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI PARSHOTTAM RUPALA)

(a): Yes, Madam. India is the largest producer of sesame seeds in the world and produced 0.81 million tonnes during 2014.

Contd...2/-

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3899

09 अगस्त, 2016 को उत्तरार्थ

विषय: तिल के बीजों का उत्पादन

3899. श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री एस.आर. विजय कुमारः

श्री टी. राधाकृष्णनः

श्री कुँवर हरिवंश सिंहः

क्या कृषि और कृषक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): क्या भारत विश्व का सबसे बड़ा तिल के बीजों का उत्पादक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख): पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कमायी गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग): क्या कुछ देश भारतीय तिल के बीजों में उगाने के समय अत्यधिक कीटनाशक और नाशक कीटमार प्रयोग के कारण आयात करने के अनिच्छुक हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ): सरकार द्वारा किसानों को अनुमत्य वैश्विक मानकों के अनुसार कीटनाशकों व नाशक कीटमार प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ): तिल के बीजों की जैविक कृषि करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं/गए हैं/उठाए जाने हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला)</u>

(क): जी हां। भारत विश्व में तिल के बीजों का सबसे बड़ा उत्पादक है और वर्ष 2014 के दौरान 0.81 मिलियन टन का उत्पादन हुआ।

(b): Foreign exchange earned by the Government on the export of sesame seed during the last three years and current year is as under:

Years	Quantity (tonnes)	Value (million US $)
2013-14	2,57,441	592.17
2014-15	3,75,656	772.27
2015-16	3,28,373	459.65
2016-17 (April-May, 2016)	69,094	87.57

(c): The issue of rapid alert from European Union regarding Salmonella contamination in Indian sesame seed was resolved and a new procedure for control of contamination of Salmonella in sesame seeds for export to EU countries was notified by Directorate General Foreign Trade (DGFT) vide notification no. 37/2015-20 dated 03rd February, 2016. The market access issue of sesame seed, with Japan is being pursued. The issue of sesame seed export was taken up with Japanese delegation during the 3rd meeting of Joint Committee under India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) held on 28th July, 2015.

(d): The Government of India is emphasizing upon the use of right dose of pesticides/ insecticides as recommended by research organization like ICAR and SAUs. These organizations follow global norms while proposing recommendations.

(e): National Centre for Organic Farming (NCOF) under DAC&FW, is the nodal agency for promotion of organic farming in the country through technical capacity building of all the stakeholders including human resource development, transfer of technology, promotion and production of quality organic and biological inputs, awareness creation and publicity through print and electronic media.

In addition, to increase production and productivity of oilseeds, National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP) is being implemented since 2014-15. Under the mission, use of bio-agents, bio-fertilizers and bio-pesticides, which are organic in nature, are being supported for cultivation of oilseeds including sesame. Financial assistance is also being provided for supply of Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) for management of insects and Phosphate Solubilising Bacteria (PSB) and Zinc Solubilising Bacteria (ZSB), Azotobactor, Mycorrhiza etc. for organic nutrient availability.

****

(ख): पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तिल के बीज का निर्यात करके सरकार द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)
2013-14	2,57,441	592.17
2014-15	3,75,656	772.27
2015-16	3,28,373	459.65
2016-17 अप्रैल-मई 2016)	69,094	87.57

(ग): भारतीय तिल के बीज में साल्मोनेल्ला संदूषण से संबंधित यूरोपीयाई संघ की तत्काल चेतावनी के मुद्दे का समाधान कर लिया गया और विदेशी व्यापार के महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 3 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 37/2015-20 के द्वारा यूरापीयाई संघ देशों को निर्यात के प्रयोजनार्थ तिल के बीजों में साल्मोनेल्ला के संदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई प्रक्रिया अधिसूचित की गई। तिल के बीज की मंडी पहुंच के मुद्दे पर जापान को मनाया जा रहा है। 28 जुलाई, 2015 को आयोजित हुई भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत संयुक्त समिति की तीसरी बैठक के दौरान जापानी शिष्टमंडल के साथ तिल के बीज के निर्यात के मुद्दे को उठाया गया।

(घ): भारत सरकार अनुसंधान संगठनों जैसे आईसीएआर और एसएयू द्वारा संस्तुत कीटनाशकों/नाशक कीटमार की सही मात्रा का उपयोग करने पर जोर देती है। ये संगठन संस्तुतियों को प्रस्तावित करते समय वैश्विक मानदंडों का अनुसरण करते हैं।

(ड.): डीएसीएंडएफडब्ल्यू के अधीन राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ) मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी का अंतरण, गुणवत्तायुक्त जैविक व जीवविज्ञानीय आदानों का संवर्धन और उत्पादन, मुद्रित व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करने और प्रचार-प्रसार सहित सभी पणधारियों की तकनीकी क्षमता निर्माण के माध्यम से देश में जैविक खेती के संवर्धन के प्रयोजनार्थ नोडल एजेंसी है।

इसके अतिरिक्त तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत जैव-अभिकारकों, जैव-उर्वरकों और जैव-कीटनाशकों, जो जैविक प्रकृति के हैं, के उपयोग को तिल सहित तिलहनों की खेती के लिए सहायता दी जा रही है। कीटों के प्रबंधन के प्रयोजनार्थ परमाणु पॉलीहेड्रोसिस वायरस (एमपीवी) की आपूर्ति करने तथा जैविक पोषक तत्वों की उपलब्धता के प्रयोजनार्थ फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया (पीसीबी) और जिंक घुलनशील बैक्टीरिया (जैडएसबी), एजोटोबैक्टर, माइकोरिजा आदि के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

******

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2515
TO BE ANSWERED ON THE 16TH AUGUST, 2011

MINI-KIT SEEDS PROGRAMME

2515. SHRI HARISHCHANDRA CHAVAN:

Will the Minister of AGRICULTURE कृषि मंत्री
be pleased to state:

(a) whether the Union Government proposes to implement mini-kit seeds programme in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Union Government proposes to provide such mini-kit seeds free of cost to the farmers living below the poverty line; and

(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI HARISH RAWAT)

(a) & (b): The Government of India is already implementing seed minikits programme under various schemes of the Ministry of Agriculture. In order to introduce new varieties/hybrids and to encourage farmers for seed multiplication of various crops at grass root level, Government of India provides seed minikits of different field crops and fodder crops to the farmers. The seed minikits of oilseeds and maize are provided under Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Oil Palm and Maize (ISOPOM). National Food Security Mission (NFSM) provides seed minikits of rice, wheat and pulses in identified districts. Macro Management of Agriculture (MMA) and Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) provide support for crop development including supply of seeds minikits as per priorities of the States in their work plan.

(c) & (d): The Government of India provides seed minikits to all farmers including those living below poverty line free of cost under various schemes viz; ISOPOM, NFSM, MMA, RKVY and Minikit Testing Programme on fodder crops.

****

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2515
16 अगस्त, 2011 को उत्तरार्थ

विषय: मिनी-किट बीज कार्यक्रम

2515 श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में मिनी-किट बीज कार्यक्रम कार्यान्वित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसानों को बीजों की ऐसी मिनी-किटें नि:शुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत)

(क) तथा (ख): भारत सरकार कृषि मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत पहले से ही बीज मिनीकिट कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। नई किस्मों/संकरों को लागू करने तथा आधारभूत स्तर पर विभिन्न फसलों के बीज बहुलीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार किसानों को चारा फसलों तथा विभिन्न क्षेत्रीय फसलों के बीज मिनीकिट प्रदान करती है। तिलहन एवं मक्का के बीज मिनीकिट समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम के तहत प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अभिज्ञात जिलों में चावल, गेहूं तथा दालों के बीज मिनीकिट प्रदान किए जाते हैं। कृषि में बृहत प्रबंधन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उनकी कार्य योजना के अनुसार राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुरूप बीज मिनीकिटों की आपूर्ति सहित फसल विकास के लिए सहायता दी जाती है।

(ग) तथा (घ): भारत सरकार विभिन्न स्कीमों यथा- आइसोपाम, एनएफएसएम, एमएमए, आरकेवीवाई तथा चारा फसलों पर मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले किसानों सहित सभी किसानों को नि:शुल्क बीज मिनीकिट प्रदान करती हैं।

*****

O.I.H.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.582
TO BE ANSWERED ON 22/07/2016

IMPROVING THE FARMING OF PULSES AND OILSEEDS

582. SHRI MEGHRAJ JAIN:

Will the Minister of AGRICULTURE & FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government has formulated any special plan to promote the cultivation of pulses and oilseeds and to increase the productivity thereof;

(b) whether oilseed crops have been exhibited in the Krishi Vigyan Kendras of 300 districts of the country under this scheme;

(c) whether seeds and technical assistance has been provided to the farmers under this scheme; and

(d) if so, the details of assistance given to the farmers and efforts made to increase the productivity under the plan?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(SHRI PARSHOTTAM RUPALA)

(a): Yes, Sir.

(b): Yes, during 2015-16, a total of 299 ICAR-KVKs were engaged for cluster demonstration on oilseeds. In 2016-17, 423 ICAR-KVKs will demonstrate improved varieties, crop production, protection technologies of oilseeds.

(c): Yes, Sir.

(d): In order to enhance the production and productivity of pulses and oilseeds, Government of India is implementing schemes like National Food Security Mission-Pulses (NFSM) from 2007-08 and National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP) from 2014-15 in the country.

Under NFSM-Pulses and NMOOP financial assistance are provided to farmers through State Government for various interventions like:

Contd..2/-

- Production and distribution of quality seeds of new varieties
- Demonstration of improved technologies
- Distribution of bio-pesticides, weedicides, micronutrients, gypsum, lime, bio-fertilizer
- Farm machinery & implements
- Water carrying pipes, drip, sprinkler
- Capacity building of farmers.

Besides, minikits of pulses and oilseeds are distributed to the farmers free of cost mainly to introduce new varieties through State Government and Central seed agencies.

Under NFSM few new initiatives have been taken up for increasing production and productivity of pulses during 2016-17.

- 93 Seed Hubs have been created through ICAR, State Agricultural Universities and Krishi Vigyan Kendras for ensuring the availability of new variety seeds.
- 15% of the allocation of pulses under NFSM is earmarked for production of quality seeds through State Government.
- To increase the availability of breeder seed of pulses, ICAR Institute and State Agricultural universities have been supported.

Apart from NFSM and NMOOP, under Sub-Mission on Seeds and Planting Material (SMSP) of National Mission of Agricultural Extension and Technology (NMAET) a component namely "Seed Village Programme" is in operation to upgrade the quality of farm saved seed. Similarly under the component "certified seed production of pulses, oilseeds through seed village" financial assistance is available for distribution of foundation/certified seeds of pulses and for production of certified seeds of oilseeds.

****

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 582
22 जुलाई, 2016 को उत्तरार्थ

विषय : दालों और तिलहनों की खेती में सुधार किया जाना

582. श्री मेघराज जैनः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने तथा दोनों फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत देश के 300 जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्रों में तिलहन फसलों का प्रदर्शन किया गया है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीज व तकनीकी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को दी गई सहायता तथा योजना के अन्तर्गत उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला)

(क): जी हां ।

(ख): जी हां, 2015-16 के दौरान तिलहन पर कलस्टर प्रदर्शन के लिए कुल 299 आईसीएआर-केवीके को शामिल किया गया । 2016-17 में 423 आईसीएआर-केवीके तिलहन के उन्नत किस्मो, फसल उत्पादन, संरक्षित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगे ।

(ग): जी हां ।

(घ): दलहन एवं तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि करने के लिए भारत सरकार देश में 2007-08 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम) और 2014-15 से राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी) जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं ।

विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य सरकार के माध्यम से किसानों को एनएफएसएम दलहन और एनएमओओपी के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :

- नये किस्मों के गुणवत्ता बीजों का उत्पादन एवं वितरण
- उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन
- जैव-कीटनाशियों, खरपतवार, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिप्सम, चूना, जैव-उर्वरकों का वितरण
- फार्म मशीनरी एवं उपकरण
- जल वाहक पाईप, ड्रीप, स्प्रिंकलर
- किसानों का क्षमता निर्माण

इसके अलावा राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय बीज ऐजेंसियों के माध्यम से मुख्यत: नए किस्मों को लागू करने के लिए बिना मूल्य किसानों को दलहनों एवं तिलहनों के मिनीकीट्स वितरित की जाती है । एनएफएसएम के तहत 2016-17 के दौरान दलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कुछ नए कार्यकलाप किए गए हैं :

- नए किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से 93 बीज हब तैयार किए गए हैं ।
- राज्य सरकार के माध्यम से गुणवत्ता बीजों के उत्पादन हेतु एनएफएसएम के तहत दलहनों के आवंटन का 15 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है ।
- दलहनों के प्रजनक बीजों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए आईसीआर संस्थान एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता दी गयी है ।

एनएफएसएम और एनएमओओपी के अलावा राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमईटी) की बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के तहत एक घटक नामत: "बीज ग्राम कार्यक्रम" खेत पर बचाए बीज की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए प्रचालन में है । इसी प्रकार "बीज ग्राम के माध्यम से दलहनों, तिलहनों के प्रमाणित बीज उत्पादन" घटक के तहत दलहनों के आधारी/प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु और तिलहनों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है ।

*****

6

O.I.H

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.2455
TO BE ANSWERED ON 01/08/2014

EFFECT OF DELAYED MONSOON ON SOWING OF SOYABEAN

2455. SHRI PRABHAT JHA:
SHRI VIJAY GOEL:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sowing of soyabean is getting affected due to delay in Monsoon in several parts of the country including Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any immediate steps have been taken by Central Government to help soyabean growers; and

(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(DR. SANJEEV KUMAR BALYAN)

(a) & (b): Yes Sir, sowing of soyabean has been delayed due to late onset of monsoon in the country but with rainfall received during July-2014, sowing of soyabean has picked up and is still going on including in Madhya Pradesh. As on 23rd July, 2014, an area of 77.77 lakh ha has been sown under soyabean including 55.00 lakh ha in Madhya Pradesh.

(c) & (d): National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP) launched from 2014-15 envisages provisions of flexi-fund (ten percentage of the budget) to undertake mitigation/restoration activities in case of natural calamities like drought situation. An amount of Rs. 26.27 crores has been released during current year to Madhya Pradesh under NMOOP.

The States were advised to divert some area from soyabean to other crops based on the availability of seeds and climatic conditions and also to adopt other practices like seed dibbler, farm saved soyabean seeds under the prevailing situation.

****

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2455

1 अगस्त, 2014 को उत्तरार्थ

विषय: सोयाबीन की बुआई पर मानसून की देरी का प्रभाव

2455. श्री प्रभात झा:

श्री विजय गोयल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मानसून की देरी के कारण मध्य प्रदेश सहित देश के कई भागों में सोयाबीन की बुआई प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा सोयाबीन के किसानों की मदद के लिए कोई तात्कालिक कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजीव कुमार बालियान)

(क) एवं (ख) जी, हाँ, मानसून में देरी के कारण देश में सोयाबीन की बुआई में विलंब हुआ है लेकिन जुलाई, 2014 के दौरान वर्षा होने के साथ ही सोयाबीन की बुआई शुरू हो गई है और यह मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में अभी भी जारी है। दिनांक 23 जुलाई, 2014 तक मध्य प्रदेश में 55.00 लाख है. सहित 77.77 लाख है. क्षेत्र में सोयाबीन की बुवाई हुई है।

(ग) एवं (घ) वर्ष 2014-15 से शुरू किए गए राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) में सूखे की स्थिति जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में प्रशमन/पुनरुद्धार कार्यकलाप शुरू करने के लिए फ्लेक्सी-कोष (बजट का 10 प्रतिशत) का प्रावधान परिकल्पित है। वर्तमान वर्ष के दौरान एनएमओओपी के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 26.27 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

राज्यों को बीजों की उपलब्धता एवं जलवायुवीय स्थितियों के आधार पर कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की जगह दूसरी फसल उगाने तथा वर्तमान स्थिति के अंतर्गत सीड डिबलर, खेतों पर बचाए गए सोयाबीन बीज जैसी अन्य प्रणालियों को अपनाने की भी सलाह दी गई थी।

*****

AC(CA)

CA-Unit parliament question Lok Sabha and Rajya Sabha Unstarred questions 7

Lok Sabha	Unstarred	2016	2
Lok Sabha	Unsttared	2011	
Rajya Sabha	Unstarred	2016	3
Rajya Sabha	Unsttared	2014	
Rajya Sabha	Unsttared	2012	

20.9.2016

(Ashwani Kumar)
T.A.
CA-Unit, Room No. 535
Oilseeds Division

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.4675
TO BE ANSWERED ON 18/05/ 2012

MINI-KIT SEEDS PROGRAMME

4675. SHRI DILIPBHAI PANDYA:

Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government proposes to implement mini-kit seeds programme in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government proposes to provide such mini-kit seeds free of cost to farmers living below the poverty line; and

(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(SHRI HARISH RAWAT)

(a) & (b): The Government of India is already implementing seed minkits programme under various schemes of the Ministry of Agriculture. In order to introduce new varieties/hybrids and to encourage farmers for seed multiplication of various crops at grass root level, Government of India provides seed minkits of different field crops and fodder crops to the farmers. The seed minikits of oilseeds and maize are provided under Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Oil Palm and Maize (ISOPOM). Also, Macro Management of Agriculture (MMA) and Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) provide support for crop development including supply of seeds minikits as per priorities of the States in their work plan.

(c) & (d): The Government of India provides seed minikits to all farmers including those living below poverty line free of cost under various schemes viz; ISOPOM, Initiative for Nutritional Security through Intensive Millet Promotion (INSMP) programme under RKVY, Fodder & Feed Development Scheme and Central Minikit Testing Programme on fodder crops.

****

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
*****
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4675
18 मई, 2012 को उत्तरार्थ

विषय : 'मिनी किट' बीज कार्यक्रम

4675 : श्री दिलीपभाई पंडया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में 'मिनी किट' बीज कार्यक्रम का कार्यान्वयन किए जाने का विचार रखती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे के किसानों को ऐसे 'मिनी किट' बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत)</u>

(क) और (ख) भारत सरकार कृषि मंत्रालय के विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत पहले से ही बीज मिनी किट कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है । नई किस्मों/संकरों की शुरूआत करने और जमीनी स्तर पर विभिन्न फसलों के बीज बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार किसानों को विभिन्न फील्ड फसलों और चारा फसलों का बीज मिनी किट प्रदान कर रही है । समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का स्कीम आइसोपाम के अन्तर्गत तिलहन और मक्का के बीज मिनी किट प्रदान किए जाते हैं ।

साथ ही बृहत् कृषि प्रबंधन (एमएमए) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) राज्यों में उनकी कार्य योजना में प्राथमिक रूप से बीज मिनी किटों की आपूर्ति सहित फसल विकास के लिए सहायता प्रदान करते हैं ।

(ग) और (घ) भारत सरकार विभिन्न स्कीमों यथा: आइसोपाम, आरकेवीवाई के अन्तर्गत गहन कदन्न संवर्धन कार्यक्रम (आईएनएसआईएमपी) के माध्यम से पोषक तत्व सुरक्षा हेतु पहल, चारा एवं खाद्य विकास स्कीम और चारा फसल पर केन्द्रीय मिनी किट परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी किसानों को जिनमें वे किसान भी शामिल हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीज मिनी किट प्रदान कर रही है ।

*****